9

निपुण भारत मिशन के अंतर्गत समावेशी तथा समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु हरियाणा राज्य द्वारा किए जा रहे प्रयास

चेतना जठोल*

परगट सिंह जठोल**

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अन्य सभी संस्तुतियों की सफलता का आधार प्राथमिक शिक्षा है, जब तक प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ नहीं किया जाएगा तब तक देश का शैक्षिक स्तर नहीं सुधर सकता। यदि प्राथमिक स्तर पर हम सुधार लाने में सक्षम हुए तो उच्च शिक्षा के स्तर पर स्वतः ही बदलाव देखने को मिलेगा और शिक्षा में आए इस अपेक्षित बदलाव से एक बेहतर समाज का निर्माण संभव होगा। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए प्राथमिक स्तर पर निपुण भारत मिशन पूरे देश में 2021 से शुरू किया गया, ताकि विद्यार्थियों की शैक्षिक बुनियाद को सुदृढ़ किया जा सके और देश का हर बच्चा निपुण बन सके। जब सभी राज्यों के सभी विद्यार्थी निपुण लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम हो जाएँगे तो सतत विकास के चौथे लक्ष्य 'समावेशी तथा समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी के लिए सुनिश्चित करना तथा आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना' तक हमारा देश जल्द ही पहुँच सकेगा और भारतवर्ष को विकसित देशों की कतार में हम बहुत जल्द देख पाएँगे। हरियाणा राज्य में भी निपुण भारत मिशन को ध्यान में रखते हुए बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान कार्यक्रम (एफ.एल.एन.) 2021 में शुरू किया गया। इसके तहत राज्य में कई नई पहल की गई जिनके बारे में विस्तार से बताने का प्रयास प्रस्तुत लेख में किया गया है।

निपुण भारत मिशन

निपुण भारत मिशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा प्रणाली के लिए प्राथमिक स्तर पर बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल के सार्वभौमिकता को सुनिश्चित करता है जो समग्र शिक्षा अभियान के तहत भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है।

निपुण भारत

'समझ के साथ पढ़ने और संख्यात्मक ज्ञान में निपुणता के लिए राष्ट्रीय पहल' नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी है।

निपुण भारत मिशन के तहत 2026–2027 तक, कक्षा 3 के अंत तक भारत के प्रत्येक बच्चे के लिए

*ब्लॉक रिसोर्स पर्सन, खंड मातनहेल, झज्जर, हरियाणा 124 106

**सहायक आचार्य, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीस इन टीचर एजुकेशन, झज्जर, हरियाणा 124 104

आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए है।

निपुण भारत मिशन के लक्ष्य

- सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना;
- विद्यालय से बाहर रहने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में जोड़ना;
- शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करना;
- सीखने के माहौल को मजेदार और आकर्षक बनाना है।

2017 में हुए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे (एन.ए.एस.) की तुलना में 2021 में किए गए सर्वे में विद्यार्थियों के अधिगम का स्तर प्रत्येक कक्षा के लिए निम्न पाया गया। सबसे चिंताजनक विषय यह है कि माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं की तुलना में प्राथमिक कक्षाओं के स्तर में पिछले सर्वे की अपेक्षा अधिक गिरावट देखी गई। प्राथमिक स्तर के यह विद्यार्थी जैसे-जैसे उच्च कक्षाओं में जाएँगे, इनके अपेक्षित अधिगम स्तर तथा वास्तविक अधिगम स्तर में अंतर बढ़ता जाएगा जो कि एक गंभीर चिंता का विषय है। *ए.एस.ई.आर. सर्वे* (वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट) 2022 में देश के 616 जिलों के सात लाख विद्यार्थियों को शामिल किया गया था जिनकी आयु पाँच से सोलह वर्ष के बीच थी। इस सर्वे के परिणाम बताते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के पठन कौशल में काफी गिरावट आई है। जहाँ वर्ष 2018 में तीसरी कक्षा के ऐसे विद्यार्थी जो दूसरी कक्षा के स्तर की विषयवस्तु पढ़ सकते थे उनका प्रतिशत 27.3 था, वहीं 2022 में ऐसे विद्यार्थियों का प्रतिशत गिरकर 20.5 हो गया जो गुणात्मक सुधार को इंगित करता है।

रा.शै.अ.प्र.प. 2022 द्वारा एफ.एल.एन. कार्यक्रम को सुदृढ़ रूप से लागू करने के लिए बुनियादी अधिगम अध्ययन किया गया जिसमें कक्षा 3 के विद्यार्थियों के अधिगम स्तर का आकलन करके एफ.एल.एन. कार्यक्रम के मानक निर्धारित किए गए। इस अध्ययन में देश के कक्षा 3 के 10 हजार विद्यालयों के 86 हजार विद्यार्थियों को प्रतिमान के रूप में लिया गया। इसमें मुख्य रूप से विद्यार्थियों की भाषा तथा संख्या ज्ञान का आकलन किया गया। इस अध्ययन के परिणाम बताते हैं कि 51 प्रतिशत पंजाबी भाषी विद्यार्थी, 9 प्रतिशत तमिल भाषी विद्यार्थी, राष्ट्रीय मानकों से बेहतर प्रदर्शन कर पाए। बीस भाषाओं में से तमिल, कोंकणी, आसामी तथा बोडो भाषाओं का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। सभी विद्यार्थियों में केवल 42 प्रतिशत विद्यार्थी ही गणित विषय में वैश्विक मानकों तक पहुँच सके।

2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित किए गए सतत विकास लक्ष्यों को देखें तो चौथा सतत विकास लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर इंगित करता है जिसका शीर्षक है, 'समावेशी तथा समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी के लिए सुनिश्चित करना तथा आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना'। इन सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। विश्व के लगभग सभी देश इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास करने के लिए कटिबद्ध हैं। भारत भी विकसित देशों की श्रेणी में आने और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा— बुनियादी स्तर (एन.सी.एफ.-एफ.एस.) 2022 व नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन (एन. सी.एफ.-एस.ई.) 2023 विद्यालय शिक्षा इन्हीं प्रयासों के नतीजे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में यदि तरक्की होती है तो अन्य बहुत से क्षेत्रों में देश का अच्छा प्रदर्शन करने की संभावना होती है, इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि सबसे पहले देश में शैक्षिक स्तर पर ध्यान दिया जाए। शिक्षा की बुनियाद है प्राथमिक शिक्षा, जिस पर सबसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है जिसके लिए भारतवर्ष में कई राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय शैक्षिक मिशन तथा योजनाएँ चलाई जा रही हैं। रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा इस बार बुनियादी स्तर के लिए अलग से पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाई गई है जिससे यह पता चलता है कि सबसे अधिक फोकस इस बार शिक्षा की बुनियाद को सुदृढ़ करने पर है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सबसे अधिक ध्यान बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान की ओर देने की बात कही गई है जिसके अंतर्गत सबसे पहले प्राथमिक स्तर पर बच्चों की शैक्षिक नींव को मजबूत बनाने पर बल दिया गया है। यदि नींव मज़बूत होगी तो बच्चों के आगे पढ़ने में समस्या नहीं आएगी और बच्चे शिक्षा अधूरी (ड्रॉपआउट) नहीं छोड़ेंगे। यदि पिछले एक दशक में किए गए विभिन्न उपलब्ध सर्वेक्षणों के आँकड़े देखें तो पता चलता है कि पूरे देश में प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों का शैक्षिक स्तर बहुत ही निम्न है और इसी कारण आगे चलकर शैक्षिक रूप से पिछड़ जाने वाले विद्यार्थी ड्रॉपआउट हो जाते हैं। इन सभी स्थितियों के मद्देनज़र भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2021 में 'निपुण भारत मिशन' शुरू किया गया है। इस मिशन के तहत बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान पर ध्यान दिया जा रहा है और सभी राज्य इसके क्रियान्वयन में लगे हुए हैं। निपुण भारत मिशन के अनुसार 2026–2027 तक तीसरी कक्षा के सभी विद्यार्थी समझ के साथ पढ़ पाने में सक्षम होंगे और बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।

हरियाणा राज्य में 'निपुण भारत मिशन' के तहत चलने वाले कार्यक्रम बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान (एफ.एल.एन.) की शुरुआत 2021 में राष्ट्रीय मिशन की घोषणा के साथ ही उसी वर्ष हो गई थी। हरियाणा में इस मिशन के उद्देश्यों की प्राप्ति को लेकर काफी प्रयास किए जा रहे हैं और हरियाणा ने यह लक्ष्य एक साल पहले ही यानि 2025 तक प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए हरियाणा राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, खंड स्तरीय तथा संकुल स्तरीय कार्यक्रम बड़े ही सुनियोजित ढंग से चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों का लेखा-जोखा आप निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं—

क्रियान्वयन इकाइयों का निर्माण— 'निपुण हरियाणा कार्यक्रम' को योजनाबद्ध तरीके से क्रियान्वित करने के लिए राज्य में प्रत्येक स्तर पर क्रियान्वयन इकाइयों का गठन किया गया है। राज्य स्तर पर एस.पी.आई.यू. यानि राज्य परियोजना क्रियान्वयन इकाई, जिला स्तर पर डी.पी.आई.यू. यानि जिला परियोजना क्रियान्वयन इकाई, खंड स्तर पर बी.पी.आई.यू. यानि खंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई तथा क्लस्टर स्तर पर

सी.पी.आई.यू. यानि क्लस्टर परियोजना क्रियान्वयन इकाई का गठन किया गया है। इन इकाइयों का प्रमुख कार्य राज्य में विभिन्न स्तरों पर एफ.एल.एन. कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है।

जिला एफ.एल.एन. समन्वयक की नियुक्ति— हरियाणा के प्रत्येक जिले में एफ.एल.एन. समन्वयकों की नियुक्ति की गई है, जोकि प्रमुख रूप से निपुण हरियाणा कार्यक्रम को देखते हैं तथा जिले के सभी खंडों और राज्य के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं। अपने जिले की पूरे वर्ष की एफ.एल.एन. कार्यक्रम की रूपरेखा का निर्माण भी इन समन्वयकों द्वारा किया जाता है। सभी समन्वयक प्रत्येक माह अपने-अपने जिले के हितधारकों से मीटिंग करके उनके क्षेत्र में होने वाले श्रेष्ठ कार्यों का तथा इस दिशा में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करते हैं तथा राज्य स्तर पर भी इसे साझा करते हैं।

शिक्षक प्रशिक्षण— निपुण हरियाणा मिशन की शुरुआत से ही सभी प्राथमिक अध्यापकों तथा मैंटर्स के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जिसमें शिक्षकों को निपुण लक्ष्यों की प्राप्ति को संभव बनाने के लिए उन आयामों पर प्रशिक्षित किया जा रहा है जिससे विद्यार्थी के शिक्षण-अधिगम को सृजनात्मक, गतिविधि और खेल आधारित बनाया जा सके। प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाले इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आज के डिजिटल युग की माँग के अनुसार अध्यापकों को नई तकनीक और डिजिटल संसाधनों का प्रयोग करने में भी सक्षम बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शिक्षकों को कम लागत की शिक्षण-अधिगम सामग्री बनाने के लिए भी प्रेरित किया जाता है।

पुस्तकें तथा टी.एल.एम.— निपुण कक्षाओं के लिए आकर्षक चित्रों तथा अभ्यास कार्य से सुसज्जित पुस्तकों का निर्माण किया गया है। इन पुस्तकों के प्रयोग के लिए सभी शिक्षकों को शिक्षक संदर्शिका भी प्रदान की गई है जिसमें वार्षिक, साप्ताहिक तथा दैनिक योजना के अनुसार पाठ्यचर्या को बाँटा गया है, ताकि शिक्षकों को सुविधा हो सके। इसके अतिरिक्त सभी विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए शिक्षण-अधिगम सामग्री भी पहुँचाई गई है, ताकि कक्षा-कक्ष को प्रिंट समृद्ध बनाया जाए और विद्यार्थियों की रचनात्मकता को बढ़ावा मिले।

डिजिटल संसाधनों का प्रयोग— राज्य के सभी प्राथमिक शिक्षकों तथा मैंटर्स को टैब प्रदान किए गए हैं ताकि उन्हें ऑनलाइन कार्य करने में कोई समस्या न आए। राज्य के शिक्षकों के लिए निपुण टीचर एप, मैंटर्स के लिए निपुण मैंटर एप और अधिकारियों के लिए मॉनिटर एप बनाई गई है जिसमें निपुण कक्षाओं संबंधी संसाधन सभी के द्वारा देखे जा सकते हैं। पूरे राज्य का विद्यालयवार ब्योरा इन एप्स पर उपलब्ध है। विद्यार्थी की प्रगति को जाँचने का भी यह एक सशक्त माध्यम है। पूरे राज्य के विद्यार्थियों का आकलन भी निपुण टीचर एप के माध्यम से ही किया जाता है। इन आँकड़ो को आधार बनाकर (उपचारात्मक) कार्य की योजना भी तैयार की जाती है। इसके साथ ही निपुण डैशबोर्ड भी बनाया गया है जिस पर निपुण कक्षाओं

के विद्यालय, खंड, जिले तथा राज्य-स्तरीय आँकड़े देखे जा सकते हैं।

प्रतियोगिताओं का आयोजन— विद्यार्थियों तथा अध्यापकों के लिए राज्य, जिला, खंड तथा विद्यालय स्तर पर कई प्रतियोगिताओं तथा गतिविधियों का आयोजन, निपुण हरियाणा मिशन के तहत प्रोत्साहन देने के लिए किया जाता है। विद्यार्थियों के लिए रामलीला का मंचन, माँ के नाम पत्र, शिक्षक के नाम पत्र, पहाड़े सुनाना, उल्टी गिनती सुनाना प्रतियोगिता, प्रवाहपूर्ण पठन आदि प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। साथ ही शिक्षकों के लिए भी पहाड़े सुनने, प्रवाहपूर्ण पठन करने, प्रश्नोत्तरी (क्विज) और बालगीत लिखने जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है।

अभिभावक तथा समुदाय की भागीदारी— राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा— बुनियादी स्तर के दसवें अध्याय में अभिभावकों तथा समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में चर्चा की गई है। अभिभावकों तथा समुदाय को निपुण हरियाणा मिशन से जोड़ने के लिए राज्य में कई प्रयास किए जा रहे हैं। घर-घर जाकर, विद्यार्थियों और अध्यापकों द्वारा रैली निकालकर तथा एस.एम.सी. प्रशिक्षण के माध्यम से निपुण हरियाणा मिशन में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। गतिविधि-आधारित पी.टी.एम. आयोजित करके अभिभावकों को ज्यादा से ज्यादा विद्यालय में आने के लिए प्रेरित किया जा रहा है ताकि बच्चे की प्रगति में वह भी महत्वपूर्ण योगदान दें।

एंडलाइन सर्वे— 'राज्य में निपुण हरियाणा कार्यक्रम' की प्रगति जाँचने के लिए प्रत्येक वर्ष के अंत में एंडलाइन सर्वे किया जाता है जिसमें पारदर्शिता लाने के मकसद से यह कार्य एक थर्ड पार्टी को सौंपा जाता है। वर्ष 2023 का एंडलाइन सर्वे 1–175 विद्यालयों के कक्षा 1–3 के 27,154 विद्यार्थियों के न्यायदर्श पर किया गया था। सर्वे के परिणाम सभी जिलों में हितधारकों के समक्ष प्रस्तुत किए गए, विद्यार्थियों की प्रगति में आने वाली बाधाओं पर चर्चा की गई तथा आने वाले सत्र के लिए रोडमैप भी तैयार किया गया। प्रत्येक वर्ष ऐसा सर्वे निपुण लक्ष्यों की प्राप्ति के परिणामों को दर्शाएगा और यह बताएगा कि हरियाणा राज्य के कितने प्रतिशत विद्यार्थी निपुण लक्ष्यों तक पहुँचने में सफल हो पाए हैं।

निष्कर्ष

हरियाणा राज्य द्वारा हर विद्यार्थी को निपुण बनाने की दिशा में कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिनकी प्रभावशीलता का परिणाम आना अभी बाकी है, इसलिए यह बहुत जरूरी है कि इन प्रयासों का निरंतर आकलन भी साथ-साथ होता रहे और इससे जुड़ी समस्याओं और सर्वश्रेष्ठ कार्यों की समय-समय पर पहचान की जाए, ताकि विकास की इस राह में कोई रुकावट न आए। इन सभी उपक्रमों को यदि सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर लिया गया तो वह दिन दूर नहीं जब इसके सकारात्मक प्रभाव दिखने शुरू हो जाएँगे। उम्मीद है आने वाले सभी उपलब्धि परीक्षणों में हरियाणा के सभी विद्यार्थी अपनी कक्षा अनुसार दक्षताओं को प्राप्त करने में सक्षम होंगे जब बुनियाद इतनी मजबूत हो जाएगी तो आने वाला भविष्य स्वतः ही उज्ज्वल होगा।

संदर्भ

द इकनॉमिक टाइम्स. 2023. ए.एस.ई.आर. *2022 रिपोर्ट : लर्निंग लेवेल्स डिक्लाइन आफ्टर पैंडेमिक*. https://economictimes.indiatimes.com/industry/services/education/aser-2022-report-learning-levels-decline-after-pandemic/articleshow/97101659.cms?from=mdr

मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय. 2019. *नैस 2017 : नेशनल आचीवमेंट सर्वे*. मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली.

रा.शै.अ.प्र.प. 2022. *फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी 2022*. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली.

———. 2022. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा— बुनियादी स्तर 2022*. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली.

———. 2023. *नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023*. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली.

शिक्षा मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली.

———. 2022. *नेशनल आचीवमेंट सर्वे : नेशनल रिपोर्ट नैस 2021*. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली.